'मुखी' का तीसरा जन्मदिन गौरव का क्षण

भारत में ही जन्मी 'मुखी' दे चुकी है पांच शावकों को जन्म

भोपाल, 29 मार्च. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कूनो में जन्मी चीता 'मुखी' का तीसरा जन्म-दिन प्रदेश के साथ ही पूरे देश के वन्य-जीव संरक्षण के लिए गौरव का क्षण है. प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जन्मी भारतीय चीता 'मुखी' ने रविवार को तीन वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है. डॉ. यादव ने कहा कि 'चीता परियोजना' का भविष्य स्वर्णिम है.

उन्होंने कहा कि यह परियोजना के लिये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. चालित 'चीता परियोजना' लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है. चीता 'मुखी' की कहानी भारत में चीतों की पुनर्स्थापना के प्रयासों के दृढ़ संकल्प, श्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रबंधन और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है. कूनो नेशनल पार्क में 29 मार्च को 'मुखी' के तीसरे जन्म-दिवस के अवसर पर एक विशेष और भावनात्मक वातावरण देखने को मिला. एक नन्हे शावक से आत्म-विश्वास लबरेज फर्राटे भरती वयस्क चीता और अब एक माँ बनने तक की मुखी की यात्रा प्रेरणादायक रही है. यह यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत में चीतों के संरक्षण और पुनर्वास के प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. चीता मुखी का जन्म 29 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई 'ज्वाला' की कोख से हुआ था. वह चार शावकों के समूह में एकमात्र जीवित बची थी. भीषण गर्मी के कारण उसके अन्य तीन भाई-बहन जीवित नहीं रह सके. बाद में उसकी उचित देखभाल की गई और वह अब तक पांच शावकों को जन्म दे चुकी है.

एमएसएमई इकाइयों को होगा 169 करोड़ का अंतरण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समर्थ एमएसएमई विकसित मध्यप्रदेश की थीम पर मुख्यमंत्री निवास पर सोमवार 30 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को उनके खाते में 169.57 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण करेंगे. साथ ही स्टार्टअप को भी लगभग 28 लाख से अधिक की अनुदान राशि की प्रथम किश्त भी प्रदान करेंगे. एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव को कार्यक्रम में लघु उद्योग निगम की ओर से मंत्री काश्यप 8 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश राशि का चैक भी सौंपेंगे. मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन ईआईआर योजना अंतर्गत सहायता के रूप में प्रदेश के 43 ज़िलों के 286 स्टार्टअप्स को 3.43 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रथम क़िस्त की राशि 28.6 लाख का वितरण सिंगल क्लिक से करेंगे.

2050 स्थानों पर की जांच 2912 सिलेंडर किए जप्त

भोपाल, 29 मार्च. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मध्यप्रदेश में एलपीजी पेट्रोल, डीजल, पीएनजी एवं सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. भारत में कच्चे तेल का भी पर्याप्त भण्डार है.

प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है. अभी तक 2050 स्थानों पर जांच की गई तथा 2912 एलपीजी सिलेण्डर जब्त किये गए. साथ ही 9 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई. प्रदेश के 325 रिटेल आउटलेट की जांच कराई गई है, जिसमें 01 प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है. प्रदेश के समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को सतत रूप से पेट्रोल पंपों की जांच करने के निर्देश दिये गये हैं.

पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता

प्रदेश में आज की स्थिति में सभी ऑयल कंपनियों के पास पेट्रोल/डीजल (रूस्/ ॥स्ष्ठ) का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एवं डीजल के स्टॉक की कमी की कोई स्थिति नहीं है एवं कंपनी के डिपो से भी डीजल/पेट्रोल की लगातार कंपनी द्वारा पूर्ति की जा रही है.

नगरीय निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्तियां

768 एल्डरमैन किए गए नियुक्त

भोपाल, 29 मार्च. मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने रविवार को बहुप्रतीक्षित कदम उठाते हुए नगरीय निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्तियां कर दीं. अभी 123 नगर परिषदों में चार चार एल्डरमैन और 46 नगर पालिका परिषदों में 6-6 एल्डरमैनों की नियुक्तियां की गई हैं.

ये नियुक्तियां प्रदेश भाजपा संगठन की सिफारिश पर विधिवत तरीके से राज्य सरकार ने की हैं. माना जा रहा है कि अब शीघ्र ही शेष नगरीय निकायों में भी एल्डरमैनों की नियुक्तियां की जाएंगी. अभी नगर निगमों में भी एल्डरमैन नियुक्त होंगे. शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमन्त खंडेलवाल के बीच काफी लंबी बैठक हुई है. इसके एक दिन बाद एल्डरमैनों की नियुक्तियां संबंधी आदेश जारी हुए. अनुमान है कि अब राज्य सरकार के विभिन्न निगम और मंडलों में भी राजनीतिक नियुक्तियां संबंधी आदेश शीघ्र जारी होंगे. नगरीय प्रशासन विभाग ने 123 नगर परिषद में 492 और 46 नगर पालिका में 276 एल्डरमैन नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं.

सीएम ने नवनियुक्त एल्डरमैनों को दीं शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नगरीय निकायों में नवनियुक्त एल्डरमैनों को बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि आप सभी को शहर के समग्र विकास, सुशासन और जन-भागीदारी को बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई हैं. मुझे विश्वास है कि विकसित मध्य प्रदेश-विकसित भारत के संकल्प के साथ आप सभी अपनी ऊर्जा, अनुभव और समर्पण से अपने-अपने नगरों में प्रगति के नए आयाम जोड़ेंगे. नागरिकों की अपेक्षाओं पर शत प्रतिशत खरा उतरेंगे. नगरीय निकायों में एल्डरमैन एक तरह से सरकार की ओर से नियुक्त पार्षद हैं, जो बैठकों में हिस्सा लेकर अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है.

नवदुर्गा पर्व के दौरान पुलिस ने सुनिश्चित की सुरक्षा

भोपाल. नवदुर्गा और अष्टमी पर्व के दौरान मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर उमड़ी भारी भीड़ के बीच मध्यप्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखा. पुलिस बल लगातार तैनात रहकर श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन और सुचारु व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करता रहा. मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में पुलिस ने सेवा और संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया. ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने एक दिव्यांग श्रद्धालु को गोद में उठाकर सुरक्षित रूप से मंदिर तक पहुंचाया और उन्हें बिना किसी असुविधा के दर्शन कराए. इस मानवीय कार्य की उपस्थित श्रद्धालुओं ने सराहना की.

भोपाल समेत कई जिलों में बारिश के आसार

ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड में ज्यादा असर

भोपाल, 29 मार्च. मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम तेजी से करवट बदल रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है.

इस बदलाव का मुख्य कारण सक्रिय मौसमी तंत्र है, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ लाइन और ऊपरी वायु चक्रवात का संयुक्त प्रभाव शामिल है. पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, भिंड और दतिया में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि नर्मदापुरम में गर्मी अपने चरम पर रही. यहां अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके विपरीत पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सहित सात से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि हो सकती है. भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं. वहीं उज्जैन, इंदौर और मालवा-निमाड़ क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इस मौसम परिवर्तन का असर तापमान पर भी पड़ेगा. अनुमान है कि अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी.

भोपाल में हेमंत खंडेलवाल ने सुनी 'मन की बात'

भोपाल. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने रविवार को भोपाल मध्य विधानसभा के अरेरा मंडल के बूथ क्रमांक-229 पर कार्यकर्ताओं एवं आमजन के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का श्रवण किया. इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बरूआ, जिला प्रभारी जसवंत सिंह हांडा, पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अंशुल तिवारी, मंडल अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित, पार्षद अरविंद वर्मा, बूथ अध्यक्ष सुनिल वर्मा एवं मन की बात प्रभारी सुमित पांडे उपस्थित रहे.

एमपी की नर्सिंग स्नातक बनीं नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री

विशेष संवाददाता

भोपाल, 29 मार्च. मध्यप्रदेश की नर्सिंग शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है. प्रदेश की पूर्व नर्सिंग छात्रा निशा मेहता को नेपाल में हालिया राजनीतिक बदलाव के बाद वहां की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री नियुक्त किया गया है.

इस नियुक्ति को न केवल प्रदेश बल्कि वैश्विक नर्सिंग समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धि माना जा रहा है. एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने निशा मेहता को बधाई देते हुए कहा कि यह मध्यप्रदेश से जुड़े हर नर्सिंग छात्र-छात्रा के लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा कि पहली बार विश्व स्तर पर नर्सिंग पेशे से जुड़े किसी प्रतिनिधि को इतने महत्वपूर्ण मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इस क्षेत्र की नेतृत्व क्षमता और दक्षता को दर्शाता है. परमार ने बताया कि निशा मेहता ने वर्ष 2006 से 2010 के बीच एम्स दिल्ली से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने ग्वालियर स्थित पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से एमएससी नर्सिंग की डिग्री हासिल की.

दो दिवसीय विधायक सम्मेलन आज से

भोपाल, 29 मार्च. राष्ट्रकुल संसदीय संघ के तीन राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के युवा विधायकों का दो दिवसीय सम्मेलन 30-31 मार्च को विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है.

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यक्रम सफल एवं सुचारु रूप से संपन्न हो इस के लिये संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.इस अवसर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे. तोमर ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और युवा जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर मंथन करना है. सम्मेलन में कुल पांच सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पहले दिन तीन और दूसरे दिन दो सत्र होंगे. सम्मेलन में 45 वर्ष से कम उम्र वाले मध्यप्रदेश के 37, राजस्थान के 13 और छत्तीसगढ़ के 13 विधायक शामिल होंगे.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उपस्थित रहेंगे. अन्य सत्रों के अलावा एमआईटी पूना के चेयरमैन डॉ. राहुल वी. कराड का संबोधन होगा. समापन समारोह में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश उपस्थित रहेंगे. संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उपस्थित रहेंगे.

एक नजर में

विवाद के दौरान युवक की हत्या, मां-बेटा फरार

शहडोल. अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के पकरिया गांव में एक विवाद के दौरान युवक की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद आरोपी मां-बेटा फरार हो गए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार पकरिया गांव में कल दोपहर रेमून बाई चौधरी और उसके पुत्र शिवराम चौधरी ने मनोज साहू नामक युवक पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल मनोज साहू की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए कोतमा अस्पताल भिजवाया. प्रारंभिक जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है.

किसानों के साथ 'अन्याय' का आरोप

चौधरी ने गेहूं खरीदी में देरी पर भी उठाए सवाल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 29 मार्च. कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने रविवार को मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों से किसानों को गंभीर नुकसान हो रहा है. पीसीसी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की बदहाल स्थिति के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जिम्मेदार हैं. उन्होंने सहकारी ऋण वसूली की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग करते हुए 28 मार्च की समय-सीमा को 'अन्यायपूर्ण' बताया. चौधरी ने गेहूं खरीदी में देरी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि खरीदी 16 मार्च से शुरू होनी थी, जिसे बढ़ाकर 1 अप्रैल कर दिया गया, जिससे किसान अपनी उपज कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं. कई क्षेत्रों में खरीदी की व्यवस्था अब भी अपर्याप्त बताई गई.

उन्होंने आरोप लगाया कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल का वादा पूरा नहीं हो रहा है और किसानों को 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच ही फसल बेचनी पड़ रही है. साथ ही बिजली बिल, ईंधन की कमी और बढ़ती महंगाई पर भी चिंता जताई. चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि जल्द राहत उपाय नहीं किए गए तो कांग्रेस किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी.

राधाकृष्ण मंदिर की जमीन कब्जा मुक्त होने की उम्मीद

- अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हाई कोर्ट करेगा अंतिम सुनवाई
- चिमनगंज मंडी थाने के पीछे करोड़ों की जमीन पर कट गई झुग्गी एवेन्यू
- सिंहस्थ से पूर्व इस जमीन पर बनेगी जनहित की योजना

मौके पर कट गई झुग्गी एवेन्यू

यह जमीन बेहद महत्वपूर्ण और व्यावसायिक दृष्टि से बेशकीमती मानी जा रही है. इसी कारण समय के साथ यहां पर कई लोगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश भी की गई. मंदिर समिति और जिला प्रशासन जहां कोर्ट में आमने-सामने की लड़ाई लड़ रहा है इसी बीच मौके पर झुग्गी एवेन्यू कट गई, लोगों ने झोपड़ियां बनाकर अतिक्रमण भी कर लिया गया था. प्रशासन अब पूरे मामले की कानूनी स्थिति स्पष्ट होने के बाद जमीन को मुक्त कराने की तैयारी में है.

खाली जमीन पर बनेगी जनहित की योजना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं कि आगामी सिंहस्थ अब तक का सबसे भव्य आयोजन होगा, जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु, साधु-संत और निवेशक उज्जैन पहुंचेंगे. ऐसे में शहर में मौजूद सरकारी और सार्वजनिक जमीनों को कब्जे से मुक्त कराकर उन्हें योजनाबद्ध विकास के लिए उपयोग में लाने की दिशा में सरकार और प्रशासन सक्रिय नजर आ रहे हैं.

नवभारत न्यूज

उज्जैन. चिमनगंज मंडी थाने के पीछे आगर रोड पर स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर की बेशकीमती जमीन को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है. करोड़ों रुपये मूल्य की इस जमीन पर स्वामित्व, कब्जे और राजस्व अभिलेखों में कथित हेरफेर को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है. अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इंदौर हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी.

राधा कृष्ण मंदिर की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. पुजारी के निधन के बाद उनके वारिसों द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद से इस प्रकरण में लगातार स्टे आदेश प्रभावी रहा. इसी कारण प्रशासनिक स्तर पर जमीन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी.

कोर्ट ने कहा सरकार अपनी जमीन बचाए-इस बीच इंदौर हाई कोर्ट ने मार्च माह में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जहां भी सरकारी या सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा है, वहां से अतिक्रमण हटाकर जमीन को पुनः शासन के नियंत्रण में लिया जाए. न्यायालय ने यह भी कहा है कि ऐसी जमीनों का उपयोग जनहित की योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए.

दस्तावेजों में हेराफेरी की जांच-चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के पीछे स्थित राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की यह जमीन भी इसी संदर्भ में प्रशासन की प्राथमिकता में आ गई है. बताया जा रहा है कि जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी कर स्वामित्व को लेकर विवाद खड़ा किया गया था. इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम स्तर पर विस्तृत जांच कराई जा रही है. राजस्व रिकॉर्ड की पड़ताल के साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में जमीन का नामांतरण या प्रविष्टियां बदली गईं.

छुट्टियों से टला मामला -यह मामला फिलहाल इंदौर हाई कोर्ट में विचाराधीन है. न्यायालय में इसकी अंतिम सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की संभावना है. अदालत की छुट्टियों के कारण फिलहाल सुनवाई टल गई है, लेकिन अगली तारीख पर इस प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय आने की उम्मीद जताई जा रही है. यदि न्यायालय का निर्णय प्रशासन के पक्ष में आता है तो जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर पुनः मंदिर समिति या शासन के अधिकार में दर्ज करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है.

चिंता | कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार को घेरा

19.12 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 29 मार्च. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जल संसाधन विभाग में कथित बड़े वित्तीय घोटाले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है.

पटवारी ने कहा कि विभागीय अधिकारियों ने गणना में हेरफेर, आधार महीनों का मनमाना चयन और सूचकांकों में बदलाव कर ठेकेदारों को 19.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान कराया, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ. अनियमितताओं का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि सिंगरौली के रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना में 8.95 करोड़ रुपये, शहडोल की भन्नी माइक्रो परियोजना में 3.14 करोड़ रुपये, दमोह में ग्रैविटी बांध निर्माण में 2.46 करोड़ रुपये, डिंडोरी की मुरकी परियोजना में 2.27 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई, जबकि सिवनी की तिलवाड़ा नहर परियोजना में 1.49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया.

उन्होंने इन गड़बड़ियों को महज लापरवाही नहीं, बल्कि 'सुनियोजित भ्रष्टाचार' करार दिया. पटवारी के अनुसार, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर गलत आधार सूचकांक लागू किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि फलोदी कंस्ट्रक्शन और गुप्ता कंस्ट्रक्शन जैसी कुछ कंपनियां बार-बार बड़े टेंडर हासिल कर रही हैं, जिससे पक्षपात की आशंका बढ़ती है. साथ ही, विभागीय कार्यों में कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कार्रवाई न होने पर चिंता जताई.

पन्ना जिले के एक अन्य मामले का उल्लेख करते हुए पटवारी ने 47 लाख रुपये के अनियमित भुगतान पर सरकार द्वारा नरम रुख अपनाने की आलोचना की. कांग्रेस ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच, दोषियों पर सख्त आपराधिक कार्रवाई, नुकसान की भरपाई और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60